श्री बसन्त साठे : मैं अपनी ड्यूटी करता हूं, आप अपनी ड्यूटी करते है ।

श्री चरण सिंह : दूसरा सवाल यह था कि जब माननीय इन्दिरा जी कोठी छोड़ कर दूसरी जगह गईं तो उनकी कोठी के अहाते के अन्दर जले हुए कागज के टुकड़े थे या नहीं थे । मैं तो उस सड़क से कम निकलता हूं, पैदल भी नहीं जाता हूं, इसलिये इसका मुझे इल्म नहीं है । हां, सफ़ाई कर्मचारी से इसका इल्म कर सकता हूं । लेकिन कोई तहकीकात मैंने इसके बारे में नहीं की है और मेरे पास पुलिस की भी कोई इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है ।

इनके जलने की बाबत मैंने सुना है या नहीं सुना है—मैं ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि कागजात, दस्तावेज और फाइलें जलने की खबरें इधर-उधर से आती है, कानों में पड़ती रहती है, उनमें कितनी सच्चाई है, मुझको मालूम नहीं है । मुझको इतना जरूर मालूम है कि मारुति कम्पनी के कारखाने की या जो उनकी इमारत है—उसकी तलाशी एक बार सी०बी०आई० ने ली थी, उनके कागजात भी देखे थे । उनको अपनी मुआमलात के मुताल्लिक जैसे "किस्सा कुर्सी का"—उसकी तहकीकात के लिये वहां जाना पड़ा, तो जो जरूरी दस्तावेज होंगे उनको अपने कब्जा में कर लिया होगा । इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है ।

यह बात ठीक है कि टाइम्ज आफ इंडिया, जिसमें माथुर साहब के मुताल्लिक खबर निकली थी शायद परसों नियुक्ति थी । उसमें एयर साहब के मुताल्लिक भी खबर निकली थी कि जिस वक्त स्टे की एप्लीकेशन उनके जेरे-तजवीज थी, उनके पास फोन आया था । मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है । कल उन्होंने उस रिपोर्ट के सिलसिले में एक लम्बा बयान दिया है । मैंने उनको पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले दिन की खबर का उसमें जिक्र था । उसमें उन्होंने एक एक-दो बातों की तरदीद की है—"अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जजमेंट मुआफिक नहीं देंगे तो आप और आपकी धर्मपत्नी का जीवन खतरे में पड़ सकता है ।" तो उन्होंने कहा है कि यह जो रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी धर्मपत्नी का जीवन खतरे में पड़ सकता है—मेरी धर्मपत्नी अब है ही नहीं, इसलिए वह केवल मेरे ही मुताल्लिक था । ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी में पढ़ा था । लेकिन उससे ऐसा मालूम होता है कि वह तस्लीम करते है, एडमिट करते है कि उनके पास फोन इस सिलसिले में धमकी का आया ।

MR. CHAIRMAN: We have had enough of discusion on this. We will now go to discuss the Report of the University Grant Commission.

16.55 hrs.

MOTION RE. REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1975-76—*cond.*

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में अपनी निश्चित धारणा यह है कि इस आयोग को पुनर्गठन करना चाहिये और इस आयोग में किसी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिये जो देश का बहुत ही एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट हो । आज जो इसके माननीय अध्यक्ष है, उनके बारे में माननीय सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र जी ने अपने विचार व्यक्त किये है । यह बड़े शर्म और खेद की बात है कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग में नियुक्त करवाया जब कि जो बेसिक क्वालीफिकेशन हिन्दी में होनी चाहिये थी, वह उनमें नहीं है । उन्होंने न हिन्दी में एम० ए० पास किया है और न ही हिन्दी में पी० एच० डी० किया है । यदि

इस बात में सत्यता है, तो बहुत ही खेद की बात है बहुत ही दुःख की बात है और बहुत ही शर्म की बात है । अगर उच्च शिक्षा को देने वाले, उच्च शिक्षा में काम करने वाले जो अध्यापक है, उनकी बेसिक क्वालीफिकेशन ही सही नहीं होगी, तो वे कभी भी अच्छे विद्यार्थी न हीं बना सकते है और इससे देश का सही ढंग से निर्माण नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध मे मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयो के कुलपतियों की जब नियुक्तिया होती है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि विश्वविद्यालयों के कुलपति केवल ऐसे ही लोगों को बनाया जाए, जो प्रतिष्ठित और एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट्स हों, उनका उस क्षेत्र से गहरा सम्बन्ध रहा हो । प्रायः यह देखा गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों में रिटायर्ड जजों को या नौकरशाहों को बैठा दिया जाता है, जो शिक्षा की व्यवस्था को सुधार की जगह पर शिक्षा के संस्थानों का वातावरण दूषित करते है । इसलिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विशेष ध्यान दें और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को इस बात का भी निर्देश दें कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा शास्त्रियों को ही वहां का कुलपति बनाया जाए ।

मान्यवर, मैं इंजीनियरिंग एजूकेशन के बारे में एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर बहुत से इंजीनियर बेरोजगार है । इसलिए इंजीनियरिंग की एजूकेशन देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम इतने ही इंजीनियर बनायें जिनको हम रोजगार दें सकें, जिनको नौकरी से ले सकें । तमाम बेरोजगार लोगों की फौज खड़ी करने से कोई लाभ नहीं है । बेहतर यह होगा कि ऐसे लोगों को जेनरल एजूकेशन, सामान्य शिक्षा दी जाए ताकि वह किसी दूसरे कार्य में लग सकें। स्पेशेलाइज्ड एजूकेशन देने के बाद उन्हें बेकार न कर दिया जाय ऐसा मेरा कहना है । स्पेशेलाइज्ड एजूकेशन लेने के बाद वे देश के लिए भार बन जाते है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस समस्या पर ध्यान दें ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो गरीब विद्यार्थियों को स्कोलरशिप्स दी जाती है, वजीफे दिये जाते है, उनकी संख्या को हमें बढ़ाना चाहिये । बहुत से गरीब विद्यार्थी है जो कि मेधावी छात्र होते है जो कि आगे पढ़ कर शिक्षा में बहुत कुछ कन्ट्रीब्यूट कर सकते है और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते है लेकिन उनको स्कोलरशिप्स नही मिलती है और उनके पास अपने साधन नही है जिनसे वे अपनी पढ़ाई को आगे चला सकें । इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को चाहिये कि विश्वविद्यालयों में आज जितनी छात्रवत्तियां दी जाती है, जितनी स्कोलरशिप्स दी जाती है उनकी संख्या में वृद्धि करें ।

मान्यवर, अध्यापकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना करनी चाहिये । आज विश्वविद्यालयों में और तमाम दूसरी जगहों पर जो अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती है, उनमें आम तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसमें ईमानदारी नही होती है । अगर एक राष्ट्रीय शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना की जाए और उस आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा ली जाए और अध्यापकगण की भर्ती की जाये, तो मैं समझता हूं कि बेहतर लोगों को यह कार्य दिया जाएगा ।

मैं इस विचार का हूं कि जो भी व्यक्ति अध्यापन का कार्य करता है वह सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होना चाहिये और

[श्री हरिकेश बहादुर]

सबसे अधिक योग्य व्यक्ति को ही अध्यापक बनाना चाहिये । आज यह देखा जाता है कि अध्यापक को समाज में जितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, चूंकि उतनी प्रतिष्ठा उन्हें नहीं मिलती, इसके साथ ही उनको सुविधायें भी अधिक नहीं मिलती है, उनकी तनख्वाह भी बहुत अधिक नहीं है, इस वजह से जो अच्छे लोग हैं वे इस कार्य में न जाकर दूसरे कार्यों में जाते है । वे लोग कारखानों में चले जाते है, दूसरी तरह के उद्योगों में चले जाते हैं जहां कि वे अधिक सुविधायें पाते है, अधिक सुख पाते हैं । यदि हमें अच्छे लोगों को, योग्यतम लोगों को अध्यापन कार्य मे लगाना है तो हमें अध्यापन कार्य को सबसे अधिक महत्व, सुख-सुविधाएं और प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी । इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि अध्यापकों का स्तर ऊंचा हो, समाज के अन्दर उन्हें सर्वाधिक सुविधायें मिलें, उन्हें सर्वाधिक वेतन मिले जिससे अच्छे लोग अध्यापन कार्य में जायें ।

17 hrs.

मान्यवर, परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आज की परीक्षा प्रणाली इस प्रकार की है जिसमें विद्यार्थी उन विषयों का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जो कि उनको पढाये जाते हैं । इसका कारण यह है कि वर्ष के अन्त में, जब कि पूरा कोर्स वे तैयार नहीं कर पाते, उसके कुछ हिस्से को ही वे तैयार कर पाते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है । इससे उन्हें अपने विषयों का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता । इसलिए मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के माध्यम से इस बात का प्रयास करे कि जो भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनका मन्थली टेस्ट हो, हर महीने में उनकी परीक्षा होनी चाहिये ताकि विद्यार्थी अपने अपने विषयों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें और उनकी जानकारी उन्हें हो ।

मान्यवर मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमें निशुल्क शिक्षा की ओर बढ़ना है तो बजाय इसके कि छात्रों की फीस बढ़ायी जाय, उसे हमें घटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह ठीक है कि निशुल्क शिक्षा का प्रश्न हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से भी सम्बन्ध रखता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए यह देखना चाहिए कि विद्यार्थियों से जो फीस ली जा रही है वह भी कम की जा रही है या नहीं ताकि हम निशुल्क शिक्षा के उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं।

गजेन्द्र गडकर आयोग की रिपोर्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन आन दी गवर्नेन्स आफ द यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो उस आयोग की सिफारिश है, उसके बारे में मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि विद्यार्थियों और छात्रों को पूरा प्रतिनिधित्व सिनेट, सिण्डीकेट और एक्जिक्यूटिव काऊंसिल में मिलना चाहिए । जहा तक एकाडेमिक काऊंसिल का सवाल है इसके बारे में मेरी अपनी राय है कि आयोग की रिपोर्ट को मानना चाहिए। एमर्जेंसी के दौरान छात्र संघों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। सभी छात्र संघों के कार्यकलापों को फिर से रिवाइव किया जाए, और छात्र संघों के चुनाव कराये जाएं, यह मेरा कहना है।

सिलेबस के बारे में मेरा कहना यह है कि आजकल विद्यार्थियों को ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है जिनका कि उनके मुख्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता। ऐसे भी विषय छात्रों को पढ़ाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर केमिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को सिविल इंजीनियरिंग सर्वे पढ़ाया जाता है जबकि इसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं होता। मिकेनिकल इंजीनियरिंग के

विद्यार्थियों को कैमिस्ट्री पढ़ायी जाती है। इण्टरमीडिएट और इण्टरमीडिएट तक छात्रों का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राविधिक का ज्ञान हो जाता है। आगे उन्हें जिन विषयों की जरूरत नहीं होगी, उन्हें वे विषय नहीं पढ़ाये जाने चाहिएं। अब हम पढ़ाने लगते है और उस पढ़ाई के साथ ऐसे विषय जोड़ दिये जाते है जिनका सीधा सम्बन्ध उस पढ़ाई के साथ नही है तो इससे छात्रों के मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझा पड़ता है और वे सही ढंग से सही जानकारी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि स्पेशलाइज्ड एजूकेशन देते समय विद्यार्थियों को वही विषय पढ़ाये जाने चाहिएं जिनकी कि छात्रों को आवश्यकता है। ऐसे ही विषय उन्हें पढ़ाइये जिससे कि उन्हें आगे के लिए तैयार किया जा सके और वे देश के निर्माण में अपने ज्ञान का उपयोग कर सही भूमिका अदा कर सकें।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि और भी अधिक कालेज ग्रामीण इलाकों में यू०जी०सी० के माध्यम से खुलवाए जाएं। गांवों में तमाम ऐसे छात्र हैं जिन के पास साधन नही है और जो बाहर आ कर पढ़ नहीं सकते हैं भरती हो कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और ज्ञानार्जन कर सकते हैं।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में मैं चाहता हूं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज खोले जाएं। आज छात्रों को इनमें नाम दर्ज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो वहां से ग्रेजुएट हो कर बाहर निकलते हैं उन सभी को नौकरी दिलाने में ये योगदान करें, नौकरी पाने के सुविधात्मक रास्तों का निर्माण करने में ये अपना योगदान करें, इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां पर साइंस फैकल्टी के रिसर्च स्कालर जो इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी में काम करते हैं उन्हें तो जूनियर फैलोशिप यू०जी०सी० का 250 रुपया महीना दिया जाता है और उसी कोर्स में जो इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी में रजिस्ट्रेशन कराते है उनको चार सौ रुपया दिया जाता है। यह जो भेदभाव है इसको समाप्त किया जाना चाहिये। एक ही कोर्स में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन पी०एच०डी० के लिए कराता है तो उसको स्कालरशिप हर जगह समान दिया जाना चाहिये। इसी तरह से मास्टर आफ टैक्नालाजी की डिग्री लेने वाले छात्र को यू०जी०सी० का जूनियर फैलोशिप चार सौ रुपया प्रति महिने का दिया जाता है किन्तु उन्हें कंटिजेंसी ग्राण्ट नहीं दी जाती है जबकि वे भी अपना थीसिस सबमिट करते हैं। जिस प्रकार अन्य कोर्सिस में पी०एच०डी० करने वाले छात्रों को कांटिजेंसी ग्राण्ट दी जाती है जब कि वे अपना थीसिस सबमिट करते है उसी तरह से मास्टर आफ इंजीनियरिंग, मास्टर आफ साइंसिस या इंजीनियरिंग, मास्टर आफ टैक्नालोजी की डिग्री लेने वालों को भी कंटिजेंसी ग्राण्ट दी जाए।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डा० कालू लाल श्रीमाली जब कुलपति थे उस समय विश्वविद्यालय में बहुत सी अनियमिततायें हुई थी, तरह तरह के भ्रष्टाचार किए गए थे, तरह तरह से लोगों को सताया गया था। मैं चाहता हूं कि इन सब मामलों की जांच करवाई जानी चाहिये और दोषी पाए जाने वाले लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां पर और अधिक होस्टल और रिसर्च फैलोशिप की व्यवस्था कराने का मंत्री महोदय यू०जी०सी० के माध्यम से प्रयत्न करें।

इण्डियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आज भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है। उसको कृषि विभाग में न रख कर शिक्षा विभाग में रखा जाए। वहां पर कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश का विकास करने को

[श्री हरिकेश बहादुर]

तमाम बड़े बड़े अनुसन्धान कार्य होते हैं। लेकिन आज वहां वैज्ञानिकों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। एक समाचार नव-भारत टाइम्स में परसों छपा था जिस में कहा गया था कि एक वैज्ञानिक श्री खन्ना आत्म हत्या करने जा रहे हैं। अगर ऐसी बातें वहां होने जा रही हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की बातो पर तत्काल ध्यान दें।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं शिक्षक रहा हूं। शिक्षा के बारे मे मैं इतना ही कहना चाहता हूं :

शिक्षक हौं सिगरे जग को ताकहूं तूं अब देति है शिक्षा।

सुदामा ने अपनी बीवी से यह कहा था जब उसने कहा था द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा मन्दिर हैं यहां पर जो परिस्थिति विद्यमान है वह ऊपर से लेकर नीचे तक भयंकर बनी हुई है। मंत्री महोदय शान्ति निकेतन के इलाके से आते है। वह इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में हरिजन नान-हरिजन का जो प्रश्न है इसको हटा दो। शिक्षा फ़्री कर दो ऊपर से नीचे तक। बिना किसी भेदभाव के देने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये। साफ दिल से मैं यह कह रहा हूं। भेदभाव बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिये। अपनी पालिसी को आप साफ करें। जनता पार्टी का मैनीफैस्टो मैं अपने पास रखे हुये हूं। बड़ी दुहाई दी जा रही है उसकी। जनता पार्टी का मैनीफैस्टो हमारे हाथ में है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने बताया कि यू० जी० सी० में कैसे कैसे लोग हैं। यहां का शिक्षा मंत्री कार्ड होल्डर था, चेयरमैन भी कार्ड होल्डर थे जिन्होंने इस देश को रूस के हवाले कर दिया। इन्दिरा गांधी के खिलाफ और चव्हाण साहब के खिलाफ यही चार्ज है। आपने ऐसे लोगों को यू० जी० सी० में बैठाया। इसलिए मैं चाहूंगा कि यू० जी० सी० को तुरन्त बदल दीजिये और वहां किसी हरिजन, बैकवर्ड क्लास के आदमी को चेयरमैन नियुक्त करें। जिनका देश में बहुमत है। आज कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार किसको सौंप दिया ? क्यों परेशान हैं। आज ही मौका मिल गया कहने का ? मैं कहता हूं कि आपके ही कारनामो ने हमको यहां बैठाया। हमारे झडे मे दो रंग है, 1857 के बाद हमने हिन्दू मुसलमान को एक साथ किया, हमारे झंडे में कोई भेद नहीं है लेकिन आपके झंडे मे सड़क है। 120 साल के बाद हमने दोनो को मिलाया है, आज हिन्दू मुसलमान का झगड़ा नही रह गया है। छोटे, बड़े हिन्दू, मुसलमान, चमार, ब्राह्मण, अफसर चपरासी सभी जनता पार्टी के शुभचिन्तक हैं, सारी पब्लिक हमारे साथ है।

श्री बसन्त साठे : बाबू जी ने तो कल उल्टा कह दिया है।

श्री शिवनारायण : मैं मूर्ति पूजक नही हूं। मैं शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि आप वीमेन्स यूनिवर्सिटी खोलें, ग्रामीण यूनिवर्सिटी खोलें ताकि हमारे लड़के सिनेमा संसार से दूर रहें। नालन्दा विश्वविद्यालय का आदर्श इस देश में पेश करें। हमने अपने मैनीफैस्टो में कहा है कि हम गांधियन फिलासफी पढ़ायेंगे। आज हमारा तरफ से गांधी टोपी पहने लोग दिखाई

बैठे हैं, लेकिन ऊपर एक भी नहीं हैं । बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाला । कांग्रेस का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया । आप से ज्यादा हमें कांग्रेस से मोहब्बत है, और इन्दिरा गांधी इस बरबादी के लिए जिम्मेदार हैं ।

आप रूरल यूनिवर्सिटी कायम करें, वीमेन्स यूनिवर्सिटी कायम करें ताकि लड़के शहर में आ कर चाय, सिगरेट और सिनेमा के पीछे न घूमें । मेरे प्रोफेसर ने कहा Everybody has come with a green note in the University. I have great objection to this Delhi University. ऐसे वाइस-चांसलर को खत्म कीजिये, अपनी किंगडम बना रखी है । चिराग तले अंधेरा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहाड़ों की खोह में ले जाइये तभी आप राम, कृष्ण, पैदा कर सकेंगे, अर्जुन जैसे मेधावी व्यक्ति हमको मिलेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन डा० मेलकोटे हमारे साथी रहे हैं, वह वयोवृद्ध नेता हैं और इस हाउस के सदस्य भी रह चुके हैं । उन्होंने बताया है कि आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको मदद की जरूरत है । इसलिए मैं आन्ध्र प्रदेश की भी वकालात करते हुये यह निवेदन करूंगा कि इस इंस्टीट्यूशन को भी मदद दी जानी चाहिए ।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री बंगाल से आते हैं जहां कि गुरु रवीन्द्र नाथ जैसे त्यागी और बलिदानी पैदा हुए हैं । हिन्दुस्तान का क्रान्तिकारी अड्डा बंगाल और पंजाब ही रहा है । हम पर बड़ी छींटाकशी की जाती है । लोग यहां अंग्रेजी का दम भरते हैं और राष्ट्र-भाषा का विरोध करते हैं । यह बड़े शर्म की बात है; डूब मरना चाहिये । दिल्ली के रामलीला मैदान में जब श्री ब्रज्नेव आये थे तो वह हिन्दी में बोले और यहां के हमारे कम्युनिस्ट नेता श्री हीरेन मुकर्जी ने अपना भाषण अंग्रेजी में किया । इसीलिए मेरा शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि भारत की शिक्षा में आमूल परिवर्तन करें । और बिना भेदभाव के प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक की फ्री एजूकेशन करें । उत्तम शिक्षा बनायें और इस देश में उत्तम शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सबको दें ।

जब कोई अंग्रेजी का विरोध करता है तो और बात है लेकिन जब राष्ट्रभाषा का विरोध किया जाता है, तो उससे मेरा खून खौलता है । सदन में राष्ट्र भाषा हिन्दी हुई है, तो हिन्दी का विरोध क्यों किया जाता है । मुझे आज भी याद है, 1906 में मुस्लिम लीग के एक नेता ने कहा था—

Those who will join hands, we will join hands. Otherwise, we will go ahead and you will miss the bus. Work while you work; play while you play. That is the way to be happy and gay.

आज हमें इस मुल्क को ऊंचा लाना है, उत्तम शिक्षा देनी है—

मातृवत्, परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः ।

ऐसे पंडित हमको दें तभी इस देश में कल्याण होगा और हिन्दू, मुस्लिम, ब्राह्मण का भेदभाव समाप्त हो जाएगा ।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय को पुनः धन्य-वाद देता हूं और आशा करता हूं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके सफल बनायेंगे ।

*SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI (Nabadwip): Mr. Chairman, Sir, I will speak in my mother tongue Bengali. Sir, this report of the U.G.C. only reiterates the policy initiated in the 5th Five Year Plan and it portrays what has been done and what is proposed to be done following that policy only. In the very first page of this report it has been said:

> "The Commission has been laying great emphasis on regulation of the growth of Universities and colleges so that standards could be raised by consolidating the existing institutions."

Then again at page 10 it says:

> "While following a policy of regulated admissions to university level courses in the interest of maintenance of standards and proper utilization of our scarce resources, specific measures like the provision of remedial courses and reservation of seats, have been adopted to ensure that students belonging to the weaker sections of the community are not denied access to higher education."

Stress has been laid on consolidation. Now the programmes under consolidation can be viewed under three heads, enrolment regulation, secondly raising the standards and thirdly to make the colleges viable. All these programmes together has been called "consolidation". it has apparently been presumed that there has been enough spread of higher education in our country and that has reached an optimum level. Now they will turn towards raising quality and standard of education. The idea is that we will educate lesser number of students but will provide them with better quality of education? Now the question is are we uniformly following this policy in respect all the students who are coming for higher education. I am afraid that is not being done. Sir, out of total 4058 colleges only 407 colleges are being brought under this quality improvement programme. That has been stated in this report itself. The selected colleges form only 10 per cent of the total number of colleges. The other 90 per cent colleges are left out of this quality improvement programme. That means the programme of consolidation is being made applicable to these 10 per cent colleges only. Along with this mention has been made of social justice. We have all along been seeing that the Government's idea of social justice means, some facilities for scheduled castes and scheduled tribes students like grant of additional facilities for research to about 50 such students, as mentioned in this report itself, and opening of a few institutions in some backward areas. It is limited to that only. The Government's idea of social justice ends there and the Government keeps a clean conscience. Then again a few things have been mentioned about flexibility and non-formal education where the Government washes itself of all responsibilities. Any one can deposit prescribed fees and take the examinations. All this is only a repetition of the earlier policies. It is only a play of terminology. In reality this official jargon is nothing but a rhetoric of crisis management. It is only an attempt to conceal the crisis in the field of education. If we go behind this rhetoric and try to probe a little what will we find? Mention has been made about consolidation and "growth". Sir, the question of "growth" is totally irrelevant. In the field of regulation of admission we find that even without any positive role of the U.G.C. regulation has been taking place. Since 1971-72 in the field of college education, it is not that the percentage of growth is declining but the absolute number of students itself is on the decline. In the U.G.C. report it has been said that the percentage of growth in the number of students for higher education is declining. This decline in the percentage of growth also varies from year

*The original speech was delivered in Bengali.

to year. It has been tactfully that said University level enrolment between 1961-62 and 1969-70 increased by 12.14 per cent. In 1970-71 it became 9.0 per cent. In 1971-72 it was 5.7 per cent, 1972-73 it was 5 per cent; 1973-74 it went down further to 3 per cent. In 1974-75 it went up little to 5.9 per cent. In 1975-76 it came to 2.5 per cent. This is really tactful and this has been repeated in the Ministry's report also. But if we consider the total number, we will find that it is constantly on the decline. In the basic statisticals relating to the Indian Economy, 1950-51 to 1974-75 which is a publication of the Department of Statistics, Ministry of Planning, it has been said that in 1971-72, the total number of students in Universities and colleges were 3.26 million. No Sir, this figure has been mentioned in this publication of the U.G.C. on the basic facts and figures. In the former publication it has been said that the total number of students in Universities and colleges in 1973-74 were 3.17 million, and in 1974-75, 2.94 million. In 1975-76 it was 2.42 million according to the Ministry's report. Then what is the growth rate? In 1973-74 as compared to 1971-72 the growth rate was minus 2.8 per cent. In 1974-75 compared to the earlier year it was minus 7.3 per cent and in 1975-76 it was minus 17.7 per cent compared to the earlier year. This shows that even before the U.G.C. took up this programme of consolidation the total number had already started declining. What is the reason for this? In the report of the Ministry "socio-economic causes" have just been touched and passed over. In the U.G.C. report it has been said that the decline is due to non-formal education etc. In our view this decline has been chiefly due to three causes *viz.*, continuous erosion in real income of the people. As a result of this people are not able to make more private investment and the expenses on education has been going down and lesser number of children are being sent for receiving higher education. Secondly, the number of educated unemployed has crossed 40 lakhs and the value of degrees have been on the decline. Therefore, lesser number of students are going up for degree education. They have lost faith that the possession of degrees will help them in finding employment. Thirdly the allocation and grants of the Government on education has also gone down in real terms. As a result of this the allocation per head of students has gone down and lesser number of students are being provided education so the number is going down without any U.G.C. plan to help it. If we add to this the new 10 plus 2 system then work of "regulation" of the U.G.C. will be absolutely completed. According to the figures of NCERT we find that out the total number of students passing out of Class IX, only 33 per cent will be able to join colleges. That will be the ultimate in "consolidation".

We find a great imbalance in the matter of college and university admissions. In the U.G.C. report it has been said that there has been a marginal decline in the field of engineering, medical and scientific education. This phenomenon is nothing new in this year's report if we study last few reports we will find that there has been such a marginal decline every year. As a result there is an absolute decline in those fields. We find positive growth only in fields of law and commerce. Now the question arises that keeping in view the economic conditions of our country, whether we want more productive skill or more service skill? Do we want to produce goods or do we want to produce services? In the present report of the U.G.C. we do not find any special effort to remedy this. If this situation continues then after some time we will turn into a nation of shopkeepers. The U.G.C. does not appear to be making any concious efforts to remedy this imbalance. Along with this it is also to be considered that over 17 per cent of our engineers are already working in foreign countries. Majority of the better students of the ITI's are also going out of the country in search of

[Smt. Bibha Ghosh Goswami]

employment. Therefore, the picture becomes much more grave.

In these circumstances the idea of "consolidation" can only mean that we are going to provide more facilities of higher education to the well to do people and to curtail educational facilities for the poorer students. Therefore, through consolidation we are discriminating against the poor in a planned way. Educational facilities are being curtailed for them and it is to hide this fact that they are talking about viable institutions. Education is being restricted under the pretext of viable institutions. In such areas where there is very little spread of education it will be extremely difficult to find viable institutes and they may take decades to have viable institutes in such areas. We should also remember that in this country more than 75 per cent of the colleges are private colleges. Majority of such colleges are finding themselves unable to prove as viable colleges and therefore they will be deprived of any Government help. In Bihar, I know, 41 colleges were declared as non-viable last year but that decision has now been postponed for one year. In West Bengal also the the situation is very serious. This year the number of students in the first year class in most of the colleges is 50 or less. In these circumstances my demand is that the Government should take over all these colleges and they should take full responsibility of these colleges. About these viable institutions also the question of social justice is being added. On the one hand education is being curtailed but at the same time it is said that for purpose of social justice 50 or 100 colleges in backward areas will be covered by the scheme and they will be given grants even if they are not viable. In the matter of social justice another fraud is being played by saying that special facilities are being provided to scheduled castes and scheduled tribes students. We find enough reason to doubt the policies of the last Government in this respect. There has been a research by the Tata Institute of Social Science on this subject and the findings are, according to this Journal of Higher Education, I quote,—

> "The Scheduled Castes continue to be educationally backward and to the extent that this is so, it will be necessary to continue special programmes for their education. However the contention that the programmes for their educational development are giving rise to new inequalities within the Scheduled Castes community is amply justified. If these inequalities are to be controlled, it will be necessary to review and revise the operation of the current programmes. The emergence of new inequalities is not the only problem that occurs. The data indicate that the performance of the students who are covered by the facilities is not altogether satisfactory. Both in their performance and their situation, the beneficiaries of present programmes lag behind their non-Scheduled Castes classmates. The situation needs to be handled with greater imagination and sensitivity than at present."

It has been stated here that Scheduled Castes and Tribes students are not going up for professional and technical courses. They are only crowding the inferior institutions. Only 5 per cent of these are able to join superior institutions and 76 per cent are going to inferior institutions. Even those who are able to join superior institutions their performance is poor. I therefore will expect that the new Government will review the policy and tackle this problem with a new outlook. Now my main question is that standing in the midst of the present acute crisis in the field of education will the new Janata Government keep on following the policies of the last Government only? In this country over 70 per cent of the people are illiterate. There is crisis both in the field of primary education and secondary education and the question of economic and social dispartities are also inseparably connected with the crisis in education.

Discrimination against the poor people in providing educational facilities has been in vogue. We must provide equal opportunities of education to all. If we follow the policy of restricted and selected enrolment then only the richer people will be benefited and the poor people will be further deprived. It will not be possible to raise the standards and "consolidation" will only remain an empty slogan. Therefore in the end I will say if we are to free our education from this vicious circle then we will have to give up this policy of discrimination. The Government will have to take the responsibility for providing education to all the students right from the primary stage to secondary and university stage. They cannot shirk their responsibility in this matter leaving the responsibility to private trusts or in the name of non-formal education. Man power plann ing will have to be undertaken tak ing the total work-force in society into account. This also is not enough. Side by side Government should provide employment to all the students coming out after training or they should provide unemployment stipends in the alternative. Only then our present system of education will become meaningful and relevant to the realities of life. I will expect from the present Government and the present Education Minister, the introduction of a new and democratic method of education, a new system giving a new direction to higher education in our country

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, यह जो उच्च शिक्षा आज कल दी जा रही है, इस के बारे में अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले जो कहा था, वह आज भी उसी ढंग से इस पर लागू होती है। उन्होंने कहा था—

> यों कत्ल के बच्चों के वह बदनाम न होता,
> अफ़सोस के फरऔन को कालिज की न सूझी।

पिछले तीस सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ घुटाला हुआ है, उस की बड़ी शर्मनाक कहानी है। करोड़ों नहीं, अरबों रुपया हायर सैकण्डरी एजूकेशन पर डाला हो गया, 11वीं जमायत को कालिजों से छीन कर स्कूलों को दिया गया। दो-तीन साल के बाद यह फैसला हुआ कि 11वीं जमायत और प्रैप का सिलेबस एक कर दिया जाय— अगर ऐसा था तो उन को अलग क्यों किया गया। इत्तिफाक से मैं उस वक्त असम्बली का मेम्बर था—मैंने उस वक्त इस की बड़ी जोरदार मुखालिफत की थी। यह सिस्टम सारे हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती लागू किया गया था और इस पर अरबों रुपया खर्च करने के बाद, अब 15–20 साल बाद इन्होंने यह कहा कि हायर सैकण्डरी सिस्टम फेल हो गया है, अब 10+2+3 का सिस्टम लागू करने वाले हैं।

अब देखने की बात यह है कि जिस वोकेशनल एजूकेशन को देने की बात ये कहते हैं—उस के लिये हमारे पास क्या साधन है? जिन विषयों की तालीम दी जानी है—उस के बारे में हमारे पास क्या स्टाफ़ है? हायर सैकण्डरी स्कूलों में भी इन्होंने इस चीज को लागू किया था कि कुछ लड़कों को तिरखान का काम, लकड़ी के काम की शिक्षा दी जाय। इस काम के लिये उस वक्त आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स के टीचर्स नियुक्त किये गये थे, लेकिन जिन टीचर्स को यह काम सिखलाना था—उन की क्या हालत थी? अगर किसी कुर्सी का ऊपर का आर्म टूट जाय, तो वह आर्ट एण्ड क्राफ्ट का टीचर उस कुर्सी के बाजू को दुरुस्त भी नहीं कर सकता था। एक मामूली तिरखान, जो 10 रुपये रोज लेने वाला है, वह कुर्सी को बना सकता है, लेकिन जो आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स का टीचर है, जिसे लकड़ी के काम को सिखाना है, कुर्सी की मरम्मत भी नहीं कर सकता था। इसी तरह से अरबों रुपया खर्च करने के बाद, कुछ स्कूलों

[चौ० बलबीर सिंह]

के बाद, मन्त्री महोदय इसी सदन में आ कर कहेंगे कि यह सिस्टम भी फेल हो गया है। जिस सिस्टम को भी हमें बनाना है, जब तक उस सिस्टम को चलाने के लिये हमारे पास टीचर्स नहीं होंगे, हमारे पास साधन नहीं होंगे, वह सिस्टम फेल हो जाएगा।

मैं इसी मौके पर एक बात मन्त्री महोदय से और कहना चाहता हूं। आज कल कहा जा रहा है—स्टूडेंट्स का एक्स्प्लोजन हो गया। यह एक नया फिकरा गढ़ लिया गया है। अभी तक तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों के बच्चे डिग्री ले कर अफसर बनते रहे, हैं, अब जब गरीबों के बच्चों ने आना शुरू किया तो कहते हैं कि एक्स्प्लोजन हो गया है और इस को रोकना चाहिए। अब बड़े फख्र से कहते हैं कि ऊंची तालीम बन्द कर दो। अब जो देहात के लोग हैं, गरीब लोग है, बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं और दूसरे हरिजन हैं, वे पढ़ने के लिए मैदान में आ गये तो कहते हैं कि एक्स्प्लोजन हो गया है। हमारी शिक्षा पद्धति को आप देखिये कि जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको तो खोल रहे हैं लेकिन कालेज खोलने में बन्दिश लगाते हैं। जब पंजाब में गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त मैं वहां पर एसेम्बली का मेम्बर था। उस वक्त मैं ने कहा था कि आप यह यूनिवर्सिटी बना रहे हो और क्योंकि यह गुरु नानक जी से सम्बन्धित है, मैं अगर कोई ऐसी बात कहूंगा तो कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन मेरा कहना उस वक़्त भी यह था कि जब एक पंजाबी यूनिवर्सिटी बनी है, तो वह इसलिए बनी थी कि पंजाबी को प्रोत्साहन मिले। पहले उन्होंने यह कहा कि दो साल में हम यह काम शुरू करेंगे लेकिन फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस था, वही पंजाबी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बन गया और जो शिक्षा का माध्यम पंजाब यूनिवर्सिटी का था, वही पंजाबी यूनीवर्सिटी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी का बनने लगा। मैंने उस समय यह अर्ज किया था कि जब आप यह यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो इस गुरु नानक यूनिवर्सिटी को ऐसी यूनिवर्सिटी बनाइए जिस में ऐसी शिक्षा दी जाए जोकि दूसरी यूनिवर्सिटियों में नहीं है और सारे हिन्दुस्तान के विद्यार्थी यहां पर शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी पढ़ाई का आप इन्तजाम करें ताकि सारे हिन्दुस्तान के लोग वहां उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आएं। वहां पर वह गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन गई और हुआ यह कि दो तीन साल के बाद तीनों यूनिवर्सिटियों के वाइस-चान्सलर्स बैठे और उन्होंने यह सोचा कि तीनों यूनिवर्सिटियों का एक ही सिलेबस हो जाए। जब ऐसी बात है तो अलहदा क्यों यूनिवर्सिटी बनाई गई। होशियारपुर का एक आदमी जलन्धर जाता है और गुरु नानक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। एक कमबाड़ा पहुंच जाता है वह पंजाबी यूनिवर्सिटी में हो जाता है और जो लुधियाना में जाता है वह पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाता है। इस तरह से 6, 7 जिलों का वह सूबा है और उस के हम ने छोटे छोटे जिले और बना दिए हैं और तीन यूनिवर्सिटियां वहां पर हैं। वे तीनों यूनिवर्सिटियां बाद में यह तय करती है कि तीनों का सिलेबस एक हो जाए। जब सिलेबस एक हो गया तो अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाने का क्या फायदा। करोड़ों रुपया लगाया गया लेकिन आखीर में यह कहा कि सिलेबस एक हो जाए। इस ढंग से हमने अब तक शिक्षा को चलाया है।

सभापति जी, मैं दो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा : मैं कई कालेज चलाता हूं, लाजा कालेज, गर्ल्स कालेज, ट्रेनिंग कालेज और इंजीनियरिंग कालेज। मैं 11 कालेज चला रहा हूं और मुझे शिक्षा का प्रैक्टिकल तजुर्बा है। आज डिगरियां कैसे प्राप्त की जाती हैं। आज

चाकू और छुरे के जोर पर डिग्रियां मिलती हैं। एग्जामिनेशन हाल में लड़का मेज पर चाकू रख देता है और एक तरफ पेपर रखता है और दूसरी तरफ किताब खोल कर नकल करना शुरू कर देता है। अगर इम्तिहान ले वाला कोई सुपरवाइजर या सुपरिन्टेन्डेंट आता है तो वह कहता है कि वह चाकू पड़ा है, आप मे मुझे रोकने की हिम्मत है? इस तरह से वह नकल मारता है और नकल मारने के बाद फर्स्ट डिवीजन और सैकेण्ड डिवीजन मे निकल आता है और दूसरा लड़का जिस को ऐसा करने का मौका नहीं मिलता है, वह थर्ड डिवीजन मे आता है। दाखले के वक्त उस को दिक्कत होती है और जिस ने नकल कर के अच्छे नम्बर पा लिये हैं उस को दाखला मिल जाता है। जिन लोगों को नकल करने का मौका नही मिलता है और जिन मे उनसे ज्यादा नम्बर पाने वालो से ज्यादा काबलियत है, वे मैदान मे पिछड़ जाते हैं और दूसरे लडके जो नकल करते हैं वे मैदान मे आ जाते हैं। इसलिए मै यह कहूंगा कि एजूकेशन मे कुछ सुधार लाना चाहिए और इम्तिहान इस ढंग से लीजिए कि जो छुरे और चाकू के बल पर आगे निकलने वाले लड़के हैं वे आगे न निकलें और जो पढ़ने वाले लडके हैं, वही आगे निकले।

इसी ढंग से सरकारी किताबों का मसला है। हमारे यहां पंजाब मे उन्होंने कहा कि हिन्दी और पंजाबी को डाइरेक्ट मैथड सिस्टम से पढ़ाना चाहिए। उन्होंने इस सिस्टम से इस को पढ़ाना शुरू किया जैसे "राम आया, श्याम गया" और यह नहीं कि हमारा यहां पहले सिस्टम में जो पैंती और महारनी होता जैसे था "घ घघा, क कका, कि स्यारी, की कियारी", उस से पढ़ाते। उस सिस्टम को छोड़ कर उन्होंने डाइरेक्ट मेथड सिस्टम से पढ़ाना शुरू किया और हमारे वजीर साहब और बड़े अधिकारी, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बाहर के मुल्कों में वहां के सिस्टम को देखने के लिए जाते थे। वहां मुल्कों में जाने के बाद वहां के सिस्टम को वे देख आते हैं और अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते कि यह सिस्टम हमारे मुल्क मे लागू हो सकेगा या नहीं, क्या हमारे पास इतने साधन हैं? अमेरिका के एक छोटे से हाई स्कूल का बजट हमारी एक यूनिवर्सिटी के बजट के बराबर है। वहा जो होता है उसकी नकल करके हम उसी चीज को यहां भी शुरु कर देते हैं जिसके लिए हमारे पास साधन होते नहीं। जिस किसी के दिमाग में जो आया वह शुरू कर दिया। हम पैसे जो पढाई के लिए दें उन्हें तजुर्बे करने के लिए न दे बल्कि उस पैसे को उन लोगों पर लगायें जिनको आगे बढ़ने का मौका है।

आजकल गुरू के लिए लड़कों में वह इज्जत नही है जो प्राचीन जमाने मे होती थी। द्रोणाचार्य ने सबसे पहले पैसा लेकर तालीम दी जिससे लडकों में गुरू के प्रति इज्जत कम हुई। आजकल के लड़के अपने गुरुओं से कहते हैं हम तो पढ़ाई का पैसा देते हैं फिर काहे की शर्म। वे कहते हैं कि हम तो फीस देते हैं और पढ़ते हैं। इस तरह गुरु और शिष्य का रिश्ता जो पहले था वह समाप्त होता जा रहा है। मैं यह नही कहता कि हमें पहले वाला सिस्टम ले आएं लेकिन हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट को यह देखना पड़ेगा कि गुरु और शिष्य मे एक अच्छा रिश्ता कायम हो। अकबर इलाहाबादी ने कहा था —

उस्ताद साहिबे फहम हों
उस्ताद जी न हों।

आजकल के टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ बैठ कर शराब पीते हैं। अगर स्कूल और कालेजों में शराब चलेगी तो हमारी तालीम कहां जाएगी। इसलिए जरूरी है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे पढ़ने वाले अपने गुरु को गुरु का दर्जा दें और गुरु भी हैं वे उस्ताद जी न हों।

MR. CHAIRMAN: Please listen to me, Mr. Lakkappa. Your two members have already taken more than 40 minutes. Now you are left with 20 minutes. There are another two speakers on your side. I am calling upon them.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta—South): We have a party meeting at six O'clock. Could you not adjourn, I shall speak to-morrow?

MR. CHAIRMAN: If you do not want to speak, I shall ask Shri Lakkappa to speak.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): This is a very interesting subject. Government has come forward to discuss University Grants Commission. It was once discussed when I was a Member.

In the introduction, it was mentioned—

> "The universities have been relatively quite during 1975-76. The Commission requested the Vice Chancellor to undertake measures for restoring normalcy in regard to the academic and examination schedule. Although more than 50 per cent of the universities were behind schedule in holding examinations in 1974-75".

You may not agree to anything on the performance of the Government, but the universities have been relatively quite in 1975-76. It is a reality. That means there are certain far reaching measures which have taken place regarding universities and its development and the academic interest so far as education system is concerned. It has been stated that Education is a State subject. No less a person than Mr. M. C. Chagla has said about this. The question was asked whether UGC is powerless. The reply was given that it was a State subject. The Forty-Second Amendment has done an important thing, namely, placing Education in the Concurrent List. Some Members attacked universities vehemently saying that they are responsible for this thing or that thing. It is most unfair to attack universities for anything and everything. I wish to emphasise that universities should be free from politics and political operations and politicalisation and it should be free from patronisation of any kind. This is my view.

Sir, university standards have come down in various ways. There is a mushroom growth of universities and the standards all-round have come down. For remedving this situation, certain measures have been suggested. The Kothari Commission has made certain suggestions. Those suggestions are still not implemented. I do hope that the hon. Minister will take certain far-reaching measures in the matter, to implement the suggestions made by the Kothari Commission, to see that university standards do not deteriorate There are certain radical reforms which are very much needed in the case of certain universities and these universities should be taken care of

It has been reported that in respect of various colleges and institutions, the funds provided have been misused and misapplied. Certain institutions are not working well. All these things have been brought to the notice of the hon. Minister but still no action has been taken in the matter.

There was a high-power committee constituted to review the working of the University Grants Commission some time back. They have reported certain things. They have said that the chief function of the commission has been distribution of money and that it is not evincing any interest in the academic field. There should be an autonomous atmosphere so far as academic education is concerned. That report has also stated about misappropriation of funds granted by the UGC. Large funds allotted for academic education, for developing and enriching the knowledge of students, have been spent on construction of palatial buildings. I will quote

one example. I heard about a certain institute which got funds which were not used properly. That is why I wish to take some time in this discussion of the U.G.C.'s Report.

About the Indian Institute of Management, Bangalore, there is a case and a judicial enquiry has been pending for a long time and when the Minister, Dr. Chunder recently visited Bangalore, he paid a visit to this Institute which thus got credit whereas there was large-scale misappropriation of funds made by the Director of this Institute. I quote:

> "The Indian Express and Kannada Prabha published in series of investigative reports from 7th to 11th June, 1977....."

Under the rule of the Janata Government, the Education Minister went to the same place where there is breeding of corruption a seat of corruption—where your money has been misused.

PROF P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Sir, I rise on a point of order. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, please sit down. Prof. Mavalankar is on a point of order.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Sir, I am on a point of order. I want to know from you whether the House is discussing the Demands for Grants of the Ministry of Education or the report of the University Grants Commission for the year 1975-76. My friend may criticise the report of 75-76, and if it is his pleasure to criticise his own, the then Government's action, he is free to do so! That is a different story.

My point of order is only this. He is referring to something which is not relevant to the Report of U.G.C. The discussion here is on the U.G.C's report. He is referring to the Indian Institute of Management, Bangalore, like that, he may go on referring to the similar institutions at Calcutta and Ahmedabad.

As far as I know the Indian Institute of Management is not one of the nine institutions which is deemed to be a University under the U.G.C. Now, whatever is not within the purview of the U.G.C. how is that relevant here? That is my point of order.

MR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): It is relevant in the sense that for instance he is reading from a newspaper report about the mismanagement of that institution which, when the Minister of Education visited Bangalore, was visited by him in spite of the knowledge or in spite of the press report that their affairs are mismanaged, this was what he was referring to.

PROF. P. G. MAVALANKAR: My point of order is that this is not within the purview of this report. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order, order.

DR. HENRY AUSTIN: It comes under the Ministry of Education. (*Interruptions*).

PROF. P. G. MAVALANKAR: But he is discussing something which is not relevant.

DR. HENRY AUSTIN: In a discussion of this nature when we are discussing the U.G.C's report it is relevant in the sense that here is a situation in which the Minister of Education has gone there and he refers to something connected with that and so, it is certainly relevant.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I would like to dispute that. Our discussion should be confined to this report only.

MR. CHAIRMAN: Prof. Mavalankar's point in short is this that the discussion refers to the report of the U.G.C. and so whatever is relevant only may be discussed here. But, Mr. Lakkappa's point is beyond that.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I am not taking objection to his criticism of corruption in public life, etc., etc. I stand for incorruptibility in our public life. What I am saying here is that if his point is regarding this particularly Institute then he should have taken the permission of the Chairman and then he should have brought this matter to the House.

But, this is not the occasion to do so. That was my point.

18 hrs.

SHRI K. LAKKAPPA: I know you are an academician whereas we are politicians, we are not academicians. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Order, order. Will you kindly sit down? The point here is that you have to keep the discussion within its relevance.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I have no quarrel with my friend, Prof. Mavalankar.

MR. CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, how much more time will you take to conclude your speech?

SHRI K. LAKKAPPA: Ten minutes.

MR. CHAIRMAN: It is already 6 O'clock. The hon'ble Member may continue his speech tommorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 21, 1977/Asadha 30, 1899 (Saka)

GMGIPND—L—1693LS—5-9-77—998